भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
18.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3808 का उत्तर

नए मंगलौर पत्तन से माल ढुलाई

3808. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने न्यू मंगलौर पोर्ट से माल ढुलाई के लिए रेल अवसंरचना में सुधार की योजना बनाई है;

(ख) न्यू मंगलौर बंदरगाह और प्रमुख अंतर्देशीय गंतव्यों के बीच मालगाड़ी रेल संपर्क की स्थिति क्या है;

(ग) इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए चल रही या प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा कुशल माल भाड़ा प्रबंधन के लिए पत्तन पर निर्बाध मल्टीमॉडल संपर्क प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) कोंकण रेलवे के भारतीय रेलवे के साथ विलय की स्थिति क्या है और विलंब का कारण क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): न्यू मैंगलोर पत्तन, दक्षिण रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत भारतीय रेल नेटवर्क के माध्यम से देश के प्रमुख अंतर्देशीय गंतव्यों से जुड़ा हुआ है।

रेल अवसंरचना में सुधार करने और कुशल माल यातायात संचालन के लिए पत्तन पर निर्बाध मल्टीमोडल संपर्कता मुहैया कराने हेतु किए गए विभिन्न उपायों में निम्नानुसार शामिल है:-

(i) पनाम्बुरू और मंगलुरु जंक्शन के बीच दोहरीकरण और विद्युतीकरण

(ii) पाडिल, जोकट्टे और मंगलुरु जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग

(iii) पनाम्बुरू में यार्ड में परिवर्तन

(iv) पाडिल और मैसूरु जंक्शन के बीच विद्युतीकरण।

इसके अलावा, हासन-मंगलुरू (183 किमी) के बीच बड़ी लाइन एकल लाइन खंड को कर्नाटक सरकार के प्रमुख हिस्से के साथ एसपीवी के माध्यम से पूर्ववर्ती मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन खंड में परिवतत करके 2006 में चालू किया गया था। यह खंड पश्चिमी घाटों को पार करता है और इसमें तीखे मोड़ और ढाल हैं। यह लाइन एक महत्वपूर्ण कड़ी है और मैंगलोर बंदरगाह को कर्नाटक के भीतरी इलाकों से जोड़ती है। एसपीवी की खराब वित्तीय स्थिति के कारण रेल मंत्रालय ने इस लाइन का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया है ताकि दोहरीकरण, विद्युतीकरण आदि जैसे क्षमता संवर्धन कार्य शुरू किए जा सकें।

तदनुसार, बेंगलुरु और मंगलुरू के बीच दोहरीकरण के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण (एफएलएस) को दो भागों अर्थात (i) मंगलुरु-हासन (247 किमी) और (ii) हासन-चिकबानवारा (बेंगलुरु) वाया कुनिगल (166 किमी) में स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, बेंगलुरु-तुमकुरू (30 किमी) के बीच तीसरी और चौथी लाइन के लिए सर्वेक्षण भी स्वीकृत कर दिया गया है।

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 47,016 करोड़ रु की कुल 3,840 किमी. लंबाई वाली 31 रेल परियोजनाएँ (21 नई लाइन, और 10 दोहरीकरण) निष्पादन और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1,302 किलोमीटर लंबाई की लाइन चालू हो गई है और मार्च 2024 तक 17,383 करोड़ रु का व्यय किया गया है। इसका सारांश निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की सं.	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई(कि.मी.)	मार्च 2024 तक किया गया व्यय (करोड़ रू. में)
नई लाइन	21	2556	395	7,592
दोहरीकरण/ मल्टीट्रैकिंग	10	1284	907	9,791
कुल	31	3,840	1,302	17,383

पिछले तीन वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली कुल 6159 किलोमीटर लंबाई की कुल 56 परियोजनाओं (19 नई लाइन और 37 दोहरीकरण) के सर्वेक्षण कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसमें मंगलुरु-हासन (247 किलोमीटर) के बीच दोहरीकरण और मंगलुरु-शोरानूर (307 किलोमीटर) के बीच तीसरी और चौथी लाइन का अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शामिल है।

कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	835 करोड़ रु./ प्रतिवर्ष
2014-24	7,559 करोड़ रु. (9 गुना से अधिक)

वर्ष 2009-14 और 2014-24 के दौरान कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाले नए रेलपथ की कमीशनिंग/बिछाने का विवरण निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन किए गए कुल रेलपथ	कमीशन किए गए औसत रेलपथ
2009-14	565 कि.मी.	113 किंमी./ प्रतिवर्ष
2014-24	1,633 कि.मी.	163 कि.मी./ प्रतिवर्ष

(ङ) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) में पांच शेयरधारक हैं जिनके नाम रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार, गोवा सरकार और केरल सरकार हैं। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1990 से कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अवसंरचना 25 वर्ष से अधिक पुरानी हो गई है, जिसके लिए सुरंगों के दोहरीकरण और पुनर्निर्माण सहित यातायात की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों में बड़े नवीनीकरण/प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय की आवश्यकता है। पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए, रेल मंत्रालय द्वारा सभी शेयरधारक राज्य सरकारें, यथा महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार, गोवा सरकार और केरल सरकार से कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अपने हिस्से के अनुसार पूंजीगत व्यय का अंशदान करने अथवा रेल मंत्रालय के पक्ष में अपना हिस्सा त्यागने के लिए संपर्क किया गया है। केवल गोवा राज्य सरकार ने अपनी हिस्सेदारी त्यागने की सहमति प्रदान की है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भारतीय रेल में शामिल होना विभिन्न कारकों और शेयरधारक राज्य सरकारों की सहमति पर निर्भर है, कि वे कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भारतीय रेल में विलय होने से पहले केंद्र सरकार के 100% स्वामित्व वाली कंपनी में परिवर्तित करने के लिए रेल मंत्रालय के पक्ष में अपनी हिस्सेदारी त्याग दें।

*****